

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 3
ANSWERED ON 22.07.2024

BOOSTING DOMESTIC SUPPLY OF CRITICAL MINERALS

3. SHRI JAGGESH:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

- a) Whether it is a fact that the country relies heavily on imports for meeting its requirement for critical minerals;
- b) Whether Government has begun work on a new policy to promote exploration and processing of critical minerals in the country;
- c) Whether the proposed new policy includes incentives at each stage of the production process; and
- d) If so, the details thereof, and other measures initiated by Government to boost domestic supply of critical minerals?

ANSWER

THE MINISTER OF COAL AND MINES
(SHRI G. KISHAN REDDY)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

**STATEMENT REFERRED IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 3 FOR ANSWER ON 22.07.2024 ASKED BY SHRI
JAGGESH REGARDING BOOSTING DOMESTIC SUPPLY OF CRITICAL
MINERALS.**

(a) Yes, India relies on imports to meet its requirement of critical minerals and imports minerals like lithium, cobalt, nickel, phosphorus, potash etc.

(b) to (d): The Central Government has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 through the MMDR Amendment Act, 2023 with effect from 17.08.2023. Through the said amendment, the Central Government has been empowered to exclusively auction mining lease and composite licence for 24 critical and strategic minerals listed in the Part-D of the First Schedule to the said Act.

Ministry of Mines, Government of India has successfully auctioned 14 blocks of critical and strategic minerals.

Besides auction of critical minerals by the Central Government, in order to further boost exploration of critical and deep-seated minerals, a new mineral concession namely, Exploration Licence has been introduced for 29 deep-seated minerals mentioned in the newly inserted Seventh Schedule to the MMDR Act. The exploration licence granted through auction shall permit the licensee to undertake reconnaissance and prospecting operations for these minerals on receipt of revenue share once mining starts in the explored blocks.

Ministry has given thrust on the enhancement of the exploration program for the critical minerals. Accordingly, during the last three years (2021-22 to 2023-24), GSI had taken up 368 mineral exploration projects on various critical and strategic minerals. During the current FS 2024-25, GSI has taken up 196 mineral exploration projects to assess the mineral potential of various critical and strategic minerals across the country.

Since inception of National Mineral Exploration Trust (NMET), a total 393 projects have been funded by NMET. Out of 393 projects, 122 projects are of critical minerals through various exploration agencies.

In order to encourage private participation in exploration, Ministry of Mines has notified 22 private exploration agencies (NPEAs). These agencies are taking up exploration projects through NMET.

National Mineral Exploration Trust (NMET) has issued two schemes for partial reimbursement of exploration expenses for holders of Composite Licences and Exploration licences. Under these Schemes, upto 50% of the exploration expenditure incurred by the licence holders are reimbursed.

In 2023, enlarging the scope of the S&T program “Promotion of Research and Innovation in Start-ups and MSMEs in mining, mineral processing, metallurgy and recycling sector (S&T-PRISM)” was introduced to fund research and innovation in start up and MSME to bridge the gap between R&D and commercialisation. During 2024, under R&D Component of Science and Technology Programme of Ministry of Mines, 10 R & D Projects related to extraction, recovery and recycling of critical minerals have been approved for taking up through various Indian Institutes and research laboratories.

भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 3
दिनांक 22 जुलाई 2024 को उत्तर देने के लिए
महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाया जाना

3. श्री जगेश:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है;

(ख) क्या सरकार ने देश में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए किसी नई नीति पर काम करना शुरू कर दिया है;

(ग) क्या प्रस्तावित नई नीति में उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में प्रोत्साहन देना शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय आरंभ किए गए हैं?

उत्तर
कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाये जाने के संबंध में श्री जगगेश द्वारा दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 3 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : जी हां, भारत महत्वपूर्ण खनिजों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है और लिथियम, कोबाल्ट, निकल, फॉस्फोरस, पोटैश आदि जैसे खनिजों का आयात करता है।

(ख) से (घ): केंद्र सरकार ने दिनांक 17.08.2023 से एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2023 के माध्यम से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है। उक्त संशोधन के माध्यम से, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-घ में सूचीबद्ध 24 महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के लिए खनन पट्टे और संयुक्त अनुज्ञप्ति की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार दिया गया है।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के 14 ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है।

केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी के अलावा, महत्वपूर्ण और गहराई में स्थित खनिजों के गवेषण को और बढ़ावा देने के लिए, एमएमडीआर अधिनियम की नई सम्मिलित सातवीं अनुसूची में उल्लिखित गहराई में स्थित 29 खनिजों के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति (एक्सप्लोरेशन लाइसेंस) नामक एक नई खनिज रियायत शुरू की गई है। नीलामी के माध्यम से प्रदत्त गवेषण अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारक को खोजे गए ब्लॉकों में खनन शुरू होने के बाद राजस्व का हिस्सा प्राप्त होने पर इन खनिजों के लिए टोही और पूर्वक्षण कार्य करने की अनुमति देगी।

मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए गवेषण कार्यक्रम को बढ़ाने पर जोर दिया है। तदुसार, पिछले तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान, जीएसआई ने विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 368 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की। वर्तमान कार्य सत्र 2024-25 के दौरान, जीएसआई ने देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खनिज संभावना का आकलन करने के लिए 196 खनिज गवेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) की स्थापना के बाद से, कुल 393 परियोजनाओं को एनएमईटी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इन 393 परियोजनाओं में से, 122 परियोजनाएं विभिन्न गवेषण एजेंसियों के माध्यम से महत्वपूर्ण खनिजों की हैं।

गवेषण में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, खान मंत्रालय ने 22 निजी गवेषण एजेंसियों (एनपीईए) को अधिसूचित किया है। ये एजेंसियां एनएमईटी के माध्यम से गवेषण परियोजनाएं शुरू कर रही हैं।

राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) ने संयुक्त अनुज्ञप्तिधारकों और गवेषण अनुज्ञप्तिधारकों के लिए गवेषण व्ययों की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए दो योजनाएं जारी की हैं। इन योजनाओं के तहत, अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा किए गए गवेषण व्यय की 50% तक प्रतिपूर्ति की जाती है।

वर्ष 2023 में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के दायरे को बढ़ाते हुए अनुसंधान एवं विकास और वाणिज्यीकरण के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए स्टार्ट-अप और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को वित्त पोषित करने के लिए “खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातुकर्म और पुनर्चक्रण क्षेत्र में स्टार्ट-अप और एमएसएमई में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना (एस एंड टी-प्रिज्म)” कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 2024 के दौरान, खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अनुसंधान एवं विकास घटक के तहत महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण से संबंधित 10 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को विभिन्न भारतीय संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से शुरू करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, the Ministry in the last many months has conducted three rounds of auctions for critical mineral blocks.

MR. CHAIRMAN: Ask your supplementary.

श्री साकेत गोखले : सर, वे अभिवादन करते हैं, मैं अपना क्वेश्चन इंट्रोड्यूस तो करूँ! In November, 2023, auctions were launched for 20 critical mineral blocks, of these, only 6 blocks have been auctioned because of lack of interest of bidders. In February and March, 2024, in two auctions, 18 critical mineral blocks...

MR. CHAIRMAN: Mr. Gokhale, there is a mechanism.

श्री साकेत गोखले : ठीक है, सर। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ था, क्या अब मैं सवाल पूछूँ?

MR. CHAIRMAN: One minute. This is for benefit of everyone. When a Question is asked, the Minister lays its reply on the Table of the House. The Members have to go through that reply and then ask the supplementary related to that question.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, it is related to critical mineral blocks only.

MR. CHAIRMAN: Ask the supplementary.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, he is praising the Prime Minister; I do not even get to introduce my question. Sir, if the question is irrelevant, you may dismiss it, but let me finish it at least.

MR. CHAIRMAN: You can praise your Chief Minister.

SHRI SAKET GOKHALE: No, I want to ask a question, I am not here for praising anybody. I am here to ask a question for the people.

MR. CHAIRMAN: Ask your supplementary.

SHRI SAKET GOKHALE: My Chief Minister does not need praise here.

MR. CHAIRMAN: Ask your supplementary.

SHRI SAKET GOKHALE: Sir, I would like to ask specifically and I would like a specific answer. What is the reason for lack of interest from bidders for auctions of critical mineral blocks and what are the steps being taken to encourage interest of bidders for critical mineral blocks which are going un-auctioned? In three auctions, there was no interest from bidders. Why is that happening?

श्री जी. किशन रेड्डी : चेयरमैन सर, 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज भारत सरकार पारदर्शिता के साथ इस मिनरल्स और माइंस को ओपन ऑक्शन में लोगों को दे रही है। हम स्टार्टअप कंपनीज़ को दे रहे हैं, एमएसएमईज़ को दे रहे हैं और जो इंटरस्टेड बिग कंपनीज़ हैं, उनको भी दे रहे हैं। मिनरल्स में अभी हम हैकेथन कर रहे हैं। हम रोड शोज़ कर रहे हैं, लोगों के पास स्वयं जाकर मीटिंग कर रहे हैं। हमने फिक्की जैसी संस्थाओं के साथ मीटिंग करके लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। अभी दो दिन पहले ही 8 नए critical minerals का ऑक्शन करके लोगों को allotment letters दे चुके हैं। भारत सरकार critical minerals पर देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काम करने का प्रयास कर रही है। मैं आपकी दृष्टि में यह लाना चाहता हूं कि in the last three years 2021-22, 2022-23, 2023-24 तक जीएसआई ने critical strategic minerals पर 368 minerals exploration projects शुरू किये हैं। इसी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जीएसआई ने 196 mine exploration projects को शुरू किया है, वैसे ही National Mineral Exploration Trust (NMET) की स्थापना के द्वारा 393 प्रोजेक्ट्स को exploration and financial assistance दी है। 393 प्रोजेक्ट्स में 122 प्रोजेक्ट्स critical minerals के हैं। हम भारत सरकार की तरफ से इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री सभापति : श्री राजीव शुक्ला।

श्री राजीव शुक्ला : सर, जैसा कि आपको पता है कि जब कोल ऑक्शन को लेकर, कोल माइन्स के ऑक्शन को लेकर हंगामा हुआ था, उसके बाद जब यह सरकार आई, तब नई सरकार ने कहा कि...

श्री सभापति : राजीव शुक्ला जी, आप बहुत अनुभवी सदस्य हैं, आप सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

श्री राजीव शुक्ला : सर, मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न ही पूछ रहा हूं। तो आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए इन्होंने एक ऑक्शन किया। उसके बाद एक सेलैक्ट कमिटी बनी, जिसका मेम्बर मैं भी थी। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने वर्ष 2014 के बाद जो कोल ऑक्शन कराए थे, उनमें से कितनी माइन्स चल रही हैं और क्या यह सही है कि आपको ज़बरदस्त कोयला इम्पोर्ट करना पड़ रहा है? हमारा foreign exchange उसमें जा रहा है, क्योंकि तमाम माइन्स में लोगों ने स्टे ले लिया है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, तो ऑक्शन ऐसा था कि उससे कोई फायदा नहीं हुआ,

बल्कि हमें कोल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो हम कितना कोल इम्पोर्ट कर रहे हैं, कितने बिलियन डॉलर का इम्पोर्ट कर रहे हैं, यह आप बताइए।

श्री जी .किशन रेड्डी : आदरणीय सभापति महोदय, यह प्रश्न माइन्स का है, कोल का नहीं है, लेकिन आपने आदेश दिया है तो ...(व्यवधान)... यह कोल का प्रश्न नहीं है, यह सिर्फ माइन्स का critical minerals का प्रश्न है, आप अगर आदेश देंगे, तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : मंत्री जी, राजीव शुक्ला जी अपने विषय को लेकर आपके कक्ष में आएंगे, तब आप इनके प्रश्न का निराकरण कीजिएगा। ...(व्यवधान)... श्री मिलिंद मुरली देवड़ा। ...(व्यवधान)... Rajeevji, it is critical minerals. ...(Interruptions)...Shri Milind Deora. ...(Interruptions)...

SHRI MILIND MURLI DEORA: Sir, the question is...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the question pertains to 'critical minerals', not 'minerals.' It is about critical minerals. Shri Milind Deora. Go ahead.

SHRI MILIND MURLI DEORA: Sir, the hon. Member is correct that this is a very critical question since it pertains to critical minerals.

MR. CHAIRMAN: Yes.

SHRI MILIND MURLI DEORA: Sir, in the reply, the hon. Minister has spoken about many critical minerals, including lithium, cobalt, nickel, phosphorus and potash. What is very important to note is that lithium, in particular, is a mineral which goes into every battery that is used for all products that we use, from mobile phones to electric cars. China, today, Sir, controls the entire supply chain of lithium. Exploration and manufacturing happens in many parts of the world, but the processing is done in China. Sir, India has become today Atmanirbhar in manufacturing of mobile phones.

MR. CHAIRMAN: Ask your supplementary.

SHRI MILIND MURLI DEORA: And, it is very, very critical for us to become Atmanirbhar also in the processing of lithium. My very pointed question to the hon. Minister is that, very recently, a very large deposit of almost 6 million tons of lithium discovered in the Jammu region. When does the Government plan to begin mining of

lithium in that region, keeping in mind the eco-sensitivities and ecological balance of that region? Thank you.

श्री जी. किशन रेड्डी : सभापति महोदय, लिथियम के बारे में जम्मू-कश्मीर में जीएसआई के द्वारा कुछ डिपॉजिट्स को आइडेंटिफाई किया गया है और जम्मू-कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर उसके ऊपर पैसे खर्च करके exploration का काम शुरू किया है। जितना जल्दी हो सके, तो exploration complete होने के बाद एक्शन करके लिथियम निकालने का काम जोरदार तरीके से चल रहा है।

श्री सभापति : क्वेश्चन नंबर 4.